बिना बरसात के ओल्ड फ़रीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव

फ़रीदाबाद (म.मो.) ओल्ड फ़रीदाबाद रेलवे स्टेशन के निकट बने अंडरपास को जलभराव के लिये अब वर्षा का इन्तजार नहीं रहता। नगर निगम ने इसे भरने के लिये सीवर के सड़े हुए सीवेज की सप्लाई शुरू कर दी है। रविवार दिनांक 28 नवम्बर को इस अंडरपास की एक लेन में करीब एक फुट से अधिक सड़ा हुआ सीवेज भर जाने से लोग एक ही लेन से आवागमन करने लगे। लेकिन, इतने भर से भी निगम को तसल्ली नहीं हुई तो अगले दिन यानी सोमवार को दूसरी लेन में भी सीवेज भर दिया गया। अब दोनों लेन में करीब डेढ़ से दो फ़ीट तक सीवेज भर गया था।

आवागमन करनेवालों को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा था। कारें आदि तो जैसे-तैसे निकल पा रही थीं लेकिन दोपहिया चालकों व पैदल चलने वालों के लिये इस गंदगी में से गुजरना बहुत ही दूभर था। दुर्गंध के साथ-साथ सीवेज के छींटे भी इन सबको झेलने पड़ रहे थे। विदित है कि यह सीवेज सप्लाई रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर, महीनों से भरे हुए सीवेज़ से हो रही है।

गांधी कॉलोनी व रेलवे स्टेशन के मध्य वाली सड़क पर बिना बरसात के अक्सर उफ़नते सीवरों का जलभराव बना रहता है। जनता द्वारा परेशान होकर हल्ला-गुल्ला करने पर, नगर निगम वाले रोते-पीटते सीवर लाइन को चालू करके कुछ राहत प्रदान करते रहते थे। परन्तु इस बार कॉलोनी वासियों का हल्ला-गुल्ला भी किसी काम नहीं आया; लिहाजा यह गंदा पानी बह कर अंडरपास में भरने लगा। सोचिये ज़रा जो पानी बह कर अंडरपास तक पहुंच गया उसकी गहराई स्टेशन के सामने वाली रोड पर कितनी होगी और वहां रहनेवाले एवं वहां से गुजरने वाले हजारों लोगों की हालत क्या होगी?

इससे भी बड़ी बात तो यह रही कि जब किसी पत्रकार ने निगमायुक्त महोदय यशपाल यादव से इस बाबत बातचीत की तो उनहोंने इस समस्या से ही अनभिज्ञता जताई, जबकि यह मसला आये दिन तमाम अखबारों आदि में प्रकाशित हो रहा है। इसके बावजूद निगमायुक्त का इस समस्या से अनभिज्ञ होना गंभीर चिन्ता का विषय तो है ही, साथ में उनकी बेशर्मी को भी दर्शाता है।

पार्किंग समस्या हल करने में नाकाम प्रशासन

फ़रीदाबाद (म.मो.) यूं तो शहर भर में बनी पार्किंग समस्या शासन-प्रशासन की असफ़लता का जीता-जागता उदाहरण है, परन्तु सेक्टर 12 स्थित अनेकों सरकारी कार्यालयों के लिये बनी पार्किंग समस्या सरकार की अक्ल के दीवालियेपन का एक बेहतरीन नमूना है।

सन् 1985 में यहां लघु सचिवालय के लिये छः मंजिला भवन का निर्माण किया गया था जिसे बाद में न्यायिक परिसर बना दिया गया। कुछ वर्ष बाद इसी के साथ नया छः मंजिला लघु सचिवालय, 'हूडा' कार्यालय व हाल ही में कराधान विभाग का कार्यालय भी बन कर तैयार हो गया। इसी बीच बहुमंजिला नई न्यायिक ईमारत भी बनकर तैयार हो गई। यानी ईमारत के बाद ईमारत बनती चली गई, जिनमें हजारों कर्मचारियों के अलावा प्रति दिन हजारों नागरिक अपने-अपने कामों के लिये आने-जाने लगे।

सैंकड़ों करोड़ की ईमारतें खड़ी करके उनमें दफ्तर चलाने वाली सरकार के कुंदजहन अधिकारियों ने कभी यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इन दफ्तरों में आने-जाने वाले लोग अपने वाहनों को खड़ा कहां करेंगे? दरअसल दुरदर्शिता के अभाव में इन अफ़सरों को पार्किंग के लिये आस-पास खुले मैदान नज़र आ रहे थे। उन अफ़सरों में यह समझ पाने की क्षमता नहीं थी कि खुले पड़े मैदान सदैव ही खुले नहीं रहेंगे। हुआ भी यही। समय के साथ-साथ खुले पड़े मैदान में सरकार के विभिन्न कार्यालय बनते चले गये। ये कार्यालय कोई एकायक नहीं बन गये। 'हूडा' के मास्टर प्लान में ये सारे मैदान किसी न किसी सरकारी कार्यालय के लिये तय कर दिये गये थे।

लिहाज़ा ज्यों-ज्यों खुले मैदान घटते चले गये त्यों-त्यों आसपास की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग होने लगी। यह पार्किंग इस हद तक बढ़ गई कि सड़कों पर वाहनों का चलना तक दूभर हो गया। यदि सरकार चलाने वालों की अक्ल से दुश्मनी न होती और दुरदर्शिता का लेशमात्र भी उनमें होता तो प्रत्येक ईमारत के नीचे एक या दो मंजिला बेसमेंट केवल वाहन पार्किंग के लिये बनाई होती तो आज वाहन पार्किंग की समस्या इस कदर विकराल होकर सामने न आती। आज इस समस्या को हल करने के लिये सरकार मल्टीपार्किंग बनाने के लिये टेंडर निकाल रही है लेकिन उन्हें लेने के लिये कोई आगे नहीं आ रहा। दरअसल टेंडर निकालने और उस पर काम कराना भी अपने आप में किसी घोटाले से कम नहीं रह गया है। इसलिये वही पार्टी टेंडर पकड़ेगी जिसका लेन-देन का सौदा शासकों से तय हो जायेगा।

बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था का नमूना इसी शहर में देखना हो तो तीन नम्बर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में देखा जा सकता है। इसकी बेशमेंट में 2500 से अधिक गाड़ियां आराम से खड़ी की जा सकती हैं।

पढ़ाई के नाम पर सिर्फ सर्वे और सख्ती के नाम पर पढ़ाई ही बंद, फिर भी 12.07 mbps की रफ्तार से मोदी निकले विश्वगुरु बनने...

विवेक कुमार

विवेक मैं आपसे आधे घंटे में बात करूँ, अभी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। आधे घंटे बाद कॉल करने पर भी जवाब मिला कि विवेक मैं शाम को बात करूँ, अभी यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। इस आपा-धापी में पड़े 63 वर्षीय व्यक्ति का नाम प्रोफेसर प्रभात बसंत है जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविध्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं।

स्मार्ट दिखने और स्मार्ट होने में अंतर होता है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही कुछ शब्दों की वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग हुई जिनमे 'स्मार्ट' भी एक शब्द है। स्मार्ट के नाम पर होने वाला हर कार्यक्रम लगभग बदसूरत ही मिलेगा और उसका चेहरा भारत की शिक्षा व्यवस्था के किसी भी प्रारूप में देखा जा सकता है जहां सरकार का सारा जोर स्मार्ट दिखने में है न की स्मार्ट होने में।

शाम को बात करने पर डॉ. प्रभात ने बताया कि कोरोना काल से ही पढ़ाने का काम लगभग ऑनलाइन हो गया और तकनीक के मामले में कमजोर लगभग सभी अध्यापकों ने खुद को अपडेट किया। इसके बाद घर से क्लास चलने लगी पर सभी का मानना है कि जो बात क्लास रूम में पढ़ाने की है उसका विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता। बावजूद इसके ऑनलाइन बेशक कोरोना जैसी आपदा में एक प्लेटफॉर्म बना है पर अब कहानी कुछ और ही होती जा रही है।

लॉकडाउन खुलने के बाद से क्लास रूम को छोड़कर बाकी सब खुल चुका है। NAAC यानी नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल के नाम से चलने वाले भारत सरकार के सर्वे कार्यक्रम में अपने संस्थान को ऊंचा ओहदा दिलवाने के लिए सभी पढ़ाने वालों को हर रोज यूनिवर्सिटी में जाकर हाजिरी लगानी जरूरी है। जबकि विद्यार्थियों को क्लास रूम में बैठा कर पढ़ाने के लिए सरकार की कोई उत्सुकता और दिलचस्पी आजतक दिखाई नहीं दी। NAAC के तहत तय मापदंडों पर जो संस्थान जैसा रैंक प्राप्त करता है सरकार से मिलने वाला फंड उसी के मुताबिक संस्था को दिया जाता है। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं का सारा जोर कागजों को मजबूत कर यह दिखाने में लगा रहता है कि हम कितने उत्कृष्ट हैं।

डॉ. बसंत की ही तरह दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर भारती जगन्नाथन का भी मानना है कि क्लास रूम में पढ़ने-पढ़ाने में सीखना और समझना एक अलग ही अनुभव है जिसे ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कर पाना संभव नहीं। क्लास रूम में होने वाली बातचीत, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से होने वाला संवाद, हंसी मजाक अध्यापक और बच्चों के बीच एक खास तरह का संबंध

स्थापित करता है। वहीं पढ़ने वाले सिर्फ अध्यापक से ही नहीं बल्कि आपसी मेलजोल और बातचीत से भी काफी कुछ सीखते-समझते हैं।

क्योंकि फिलहाल विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई करना ही बचा है तो ऐसे में सरकार की तरफ से किये गए इंतजामातों पर एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर भारती और बसंत ने बताया कि यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसने कैंपस में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की हुई है जिससे कि सभी अध्यापक एकसाथ अपनी अपनी-अपनी क्लास से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बरक्स सच्चाई यह है कि यूनिवर्सिटी में एकसाथ कई फोन ऑन होने और कनेक्ट होने से नेटवर्क जाम की समस्या इतनी गंभीर रूप से हो जाती है कि क्लास कर पाना संभव नहीं। ऐसे में प्रोफेसर बसंत को पहले अपने घर पर क्लास लेनी पड़ती है और उसी दौरान फरीदाबाद से जामिया तक का सफर मेट्रो से पूरा करना पड़ता है वह भी सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए। अगले ही पल फरीदाबाद वापस क्लास लेने आना पड़ता है,क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास ले सकने की व्यवस्था सुचारू नहीं है। इसी प्रकार नेट को लेकर और स्मार्ट फोन की उपलब्धता को लेकर कई समस्याएं हैं जिनपर किसी अन्य लेख में बात की जा सकती है। फिलहाल सरकारी दावों की पड़ताल आंकड़ों से की जाए तो बेहतर होगा।

ऑकला सर्वे 2020 के अनुसार नेट स्पीड के मामले में भारत 2 पायदान सरक कर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत से उसके पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल बेहतर साबित हुए और तो और इराक ने भी स्पीड के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। साउथ कोरिया जहां एक ओर 121mbps की स्पीड के साथ पहले स्थान पर काबिज हुआ वहीं भारत 12.07 mbps की रफ्तार से विश्वगुरु बनने का दावा कर रहा है।

इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में स्वघोषित विश्वगुरु भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। गोल पोस्ट बदल कर अगर यह संख्या 500 की जाए तो IIM अहमदाबाद और भारतीय विज्ञान संस्थान क्रमशः 415 और 459 स्थान पर हैं। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने देश के शिक्षण संस्थानों को पैसे के नाम पर बजट में 6 प्रतिशत की कटौती करते हुए 93224 करोड़ रुपये ही इस वित्तीय वर्ष में दिए हैं। सरकार के रिकार्ड को देखते हुए यह कटौती आगे जारी रहने की पूरी संभावना है। जहां सरकार को GDP का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का वैश्विक निर्देश है वहीं सरकार केवल 2.6 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है।

प्रोफेसर बसंत इतिहास पढ़ाते हैं और उसके लिए हड़प्पा कालीन अवशेषों को क्लास रूम में दिखा कर बच्चों को पाँच हजार साल पुराने भारत के मशहूर काले मृदभांड के अवशेषों को छूने का नायाब मौका देते हैं। साथ ही लाखों साल पहले बन चुके जीवाश्मों और शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले पाषाणयुगीन पत्थर के औजारों से भौतिक रूप से रूबरू करवाते थे जो अब ऑनलाइन क्लास वो भी खराब कानेक्टिविटी और सिर्फ हाजिरी मात्र के लिए कॉलेज जाने से संभव नहीं।

सरकार को न स्कूल खोलने की कोई चिंता है और न ही उससे जुड़े किसी आधारभूत संरचना को बेहतर करने में। सारा जोर कागज पर यह साबित करने में हैं कि हम कितने महान हैं। सरकार के साथ कदमताल करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 'प्रदूषण' पर सख्त होते हुए कल से दिल्ली के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दे डाले हैं। न जाने कैसा प्रदूषण है जो स्कूल की हवा में है पर घर की हवा में नहीं। शुक्र है माननीय उच्चतम न्यायालय ने सख्ती करते हुए सांस न लेने का हुक्म अभी तक नहीं सुनाया।

नाकारा मेडिकल बोर्ड, चार वर्षों में 88 शिकायतें, कार्यवाही जीरो

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों के साथ बरती गयी लापरवाही की शिकायतें सुनने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हरियाणा सरकार ने ज़िले के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय बोर्ड बना रखा है। इसमें 4 सरकारी व 4 प्राइवेट डॉक्टर होते हैं। इनमें से एक इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन की ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर हसीजा भी होती है।

सैनिक कॉलोनी निवासी तरूण चोपड़ा द्वारा लगाई गयी एक आरटीआई द्वारा पता चला है कि पहली जनवरी 2018 से नवम्बर 2021 तक के चार वर्षों में विभिन्न अस्पतालों के विरुद्ध पीड़ित मरीज़ों अथवा उनके परिजनों ने 88 शिकायतें दर्ज कराई हैं। हर शिकायत की सुनवाई के लिये शिकायतकर्ता को चार-पांच बार बोर्ड की पेशियां भुगतनी पड़ती हैं उसके बाद परिणाम निल बटा सन्नाटा। यानी 88 शिकायतों में से एक भी शिकायत इस लायक नहीं पाई गयी कि किसी अस्पताल अथवा डॉक्टर को दोषी पाकर, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय। इसका अर्थ यह निकला कि किसी भी अस्पताल के किसी भी डॉक्टर ने कभी कोई लापरवाही नहीं की, सब चंगा है।

इसके विपरीत मीडिया में आये दिन बीके अस्पताल सहित तमाम व्यापारिक अस्पतालों द्वारा की गयी लापरवाहियों के चलते मरीज़ों को बहुत कुछ भुगतना पड़ा और कइयों ने तो अपनी जान भी गंवाई। लेकिन उक्त बोर्ड की निगाह में कोई भी दोषी नहीं पाया जाता। बीके अस्पताल में तो लापरवाही की घटनाओं को लेकर आये दिन जांच बैठाये जाने की घोषणा मीडिया में आती रहती है, परन्तु उस 'जांच' का परिणाम कभी सामने नहीं लाया जाता।

दरअसल उक्त बोर्ड, सरकार ने केवल व्यापारिक अस्पतालों एवं डॉक्टरों की बांह मरोड़ने के लिये बना रखा है। शासन-प्रशासन इसके द्वारा व्यापारिक अस्पतालों पर अपनी दादागिरी बनाकर अपने निहित स्वार्थों को साधता है।

कोरोना की दोनों लहरों के दौरान तो निजी अस्पतालों ने लापरवाही एवं लूट की तमाम हदें पार कर दी थी, लेकिन किसी के भी खिलाफ़ कोई बड़ी कार्यवाही होती नज़र नहीं आई। लगभग ऐसा ही हाल डेंगू के मामलों में भी किया जा रहा है।